कारोबारी मेलों से निर्यात बढ़ाने और मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने में मिलेगी मदद, ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है एक्सपो मार्ट

नई दिल्ली।

अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए कभी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले वैश्विक मेले में हिस्सा लेने वाला भारत अब खुद ही वैश्विक मेलों का बड़ा आयोजक बन गया है। इस प्रकार के आयोजन से निर्यात प्रोत्साहन के साथ मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम व द्वारका में यशोभूमि के निर्माण से यह संभव होता दिख रहा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जनवरी से लेकर मार्च तक विभिन्न सेक्टर के वैश्विक मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3-10 जनवरी तक भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन होगा। इसमें देशभर के एमएसएमई, कुटीर उद्योग, जनजातीय हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, बुनकर हिस्सा लेंगे जहां देश-विदेश के बड़े खरीदारों से लेकर आम ग्राहक इन उत्पादों तक पहुंच पाएंगे।

ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा एक्सपो मार्ट - 8-10 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में कृषि व प्रोसेस्ड खाद्य आइटम के निर्यात को बढ़ाने के लिए इंडस फूड मेले का आयोजन होगा। इसमें 120 देशों के प्रदर्शनकारी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। यहां 2,500 से अधिक विदेशी खरीदार आएंगे। इस मेले से भारतीय किसानों को काफी फायदा मिलने की संभावना है। आगामी 1-3 फरवरी तक भारत मंडपम में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन होगा। इसमें आटोमोबाइल्स सेक्टर के वैश्विक हितधारक अपने-अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इस सेक्टर के इनोवेशन का प्रदर्शन भी इस मेले में किया जाएगा। 26 से 29 फरवरी तक भारत टेक्स के नाम से वैश्विक स्तर के टेक्सटाइल मेले का आयोजन यशोभूमि में होगा। इसमें कपास उत्पादक से लेकर फैशन उद्योग तक के 3,500 हितधारक अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे। भारत टेक्स में 3,000 से अधिक वैश्विक खरीदार के आने की उम्मीद की जा रही है। 7-11 मार्च तक आहार नामक वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन भारत मंडपम में होगा, जहां खाद्य व आवभगत सेक्टर के 1,500 से अधिक स्टाल लगाए जाएंगे। गोयल ने बताया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से वैश्विक बाजार से भारत सीधे तौर पर जुड़ पाएगा और हमारे किसान से लेकर निर्माताओं को अपने-अपने उत्पादों की नुमाइश करने का भरपूर मौका मिलेगा।

न्यूज ब्रीफ

अब तक 28 देशों ने की वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भागीदार बनने की पुष्टि, सरकार का दावा

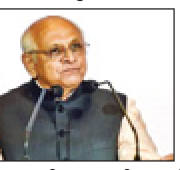

गांधीनगर (गुजरात)। अट्ठाईस देशों और 14 संगठनों ने आगामी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन (वीजीजीएस) 2024 में भागीदार बनने की पुष्टि की है। गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आधारित वीजीजीएस का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। सरकार के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चेक गणराज्य, मिस्र, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, मलेशिया, माल्टा, मोरक्को, मोजाम्बिक, नेपाल, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, रवांडा, सिंगापुर, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, घाना और वियतनाम भागीदारों के रूप में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं। साझेदार संगठनों में अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (एएमसीएचएएम इंडिया), ईपीआईसी इंडिया-यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी), इंडो-अफ्रीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो), कोरिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी शामिल हैं। सरकार ने कहा, प्रत्येक भागीदार देश और संगठन वीजीजीएस की सफलता में योगदान देकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सहयोग, व्यापार और निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के जरिए वीजीजीएस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बयान में कहा गया है, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ई-मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों पर फोकस करने के साथ निवेश को आकर्षित करने के लिए आगामी वीजीजीएस 2024 को एक प्रभावी मंच के रूप तैयार किया गया है। शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साझेदार देश और साझेदार संगठन विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूपसेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लेकर योगदान देंगे।

मार्च तक 19 लाख करोड़ हो सकता है कर संग्रह, मोदी सरकार के 10 वर्षों में तीन गुना वृद्धि की उम्मीद

नई दिल्ली। व्यक्तिगत आय तथा कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर मार्च तक 19 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। इस दौरान केंद्र में नरेंद्र मोदी दस साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इससे लोगों के लिए अनुकूल कर उपाय करने के अधिक अवसर मिलेंगे। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर (व्यक्तिगत आयकर तथा कॉरपोरेट कर) संग्रह अभी तक 20 फीसदी बढ़ा है। कर संग्रह बढ़ने की अगर यही रफ्तार रही तो 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में संग्रह करीब 19 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह 2023-24 के बजट में अनुमानित 18.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार कई वर्षों से कम दरों और कम छूट के साथ कर व्यवस्था को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। 2019 में सरकार ने छूट छोड़ने वाले कॉरपोरेट घरानों के लिए कर की कम दर का विकल्प दिया था। अप्रैल 2020 में आम करदाताओं के लिए भी इसी तरह की योजना शुरू हुई थी। चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी में पार्टनर गौरी पुरी ने कहा कि कर लेनदेन के डिजिटलीकरण और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने पर ध्यान देने से कर भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे सरकार को कर दरों को तर्कसंगत बनाने के कुछ अवसर मिलने की उम्मीद है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं

नई दिल्ली। वेश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर रहे। तेल विपणन करने वाली कंपनिपयों की वेबसाइट पर जारी दरों के अनुसार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इनकी कीमतों के यथावत रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर रहा। वैश्विक स्तर पर साप्ताहांत पर अमेरिकी क्रूड 0.61 प्रतिशत उतरकर 71.33 डॉलर प्रति बैरल और लंदन ब्रेंट क्रूड 0.09 प्रतिशत गिरकर 77.08 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। देश के चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस प्रकार रही- दिल्ली पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर, डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर, मुंबई पेट्रोल 106.31 रुपए प्रति लीटर, डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई पेट्रोल 102.73 रुपए प्रति लीटर, डीजल 94.33 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता पेट्रोल 106.03 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर है।

मजबूत जीडीपी, महंगाई-बेरोजगारी पर नकेल व आर्थिक कॉरिडोर, 2023 में विकसित भारत की ओर ऐसे बढ़े कदम

नई दिल्ली।

साल 2023 की विदाई हो रही है। इस साल भारत ने आर्थिक मोर्चे पर कई उपलब्धियां हासिल की है। साल 2023 में देश की अर्थव्यवस्था एक नए मुकाम की ओर बढ़ी है। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने की यात्रा शुरू हो गई है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद जीडीपी और महंगाई के मोर्चे पर साल 2023 में भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। साल 2023 में भारत ने जी 20 का सफल आयोजन कर दुनिया को नई राह दिखाई। वहीं इस आयोजन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के सशक्त बनने का रास्ता भी साफ हुआ।

भारत में आयोजित जी 20 समिट के दौरान भारत से यूरोप तक नया स्पाइस कॉरिडोर या आर्थिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति बनी जो एक तरह से चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का तोड़ है। हाल ही में इटली ने बीआरई प्रोजेक्ट से होने की घोषणा कर एक तरह से भारत की परियोजना के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। आइए नजर डालते हैं साल 2023 में आर्थिक मोर्चे पर भारत की उपल्बियों पर।

जीडीपी की रफ्तार बनाए रखने में सफल - तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत साल 2023 में अपनी मजबूत वृद्धि दर बनाए रखने में सफल रहा है। सकल घरेलू उत्पाद पर रेटिंग एजेंसी एसएंडपी के आंकड़ों से सकारात्मक से भी संदेश मिला है। एसएंडपी ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी का मानना है कि अर्थव्यवस्था के सामने पैदा होने वाले प्रतिकूल हालात की भरपाई मजबूत वृद्धि दर से होगी। ऐसे में जीडीपी के मोर्चे पर साल 2023 में भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। आने वाले समय में देश की जीडीपी 6 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के बीच बनी रह सकती है। भारत के केंद्रीय बैंक- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मौजूदा और अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। सरकार के मुताबिक मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी की दर से बढ़ी।

महंगाई नियंत्रण के मोर्चे पर मिली कामयाबी - महंगाई के मार्चे पर भी भारत का प्रदर्शन साल 2023 में संतोषजनक रहा। केंद्र सरकार और आरबीआई प्रतिबद्धता के साथ महंगाई दर को साल 2023 में

अधिकतर समय पर आरबीआई के बैंड चार से छह प्रतिशत के बीच बनाए रखने में सफल रहा। मौसम की चुनौतियों के कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण चिंता जरूर बढ़ी पर सरकार और आरबीआई के कदमों से इसे संतोषजनक दायरे में लाने में सफलता मिली। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को शुरुआत में बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। उनका यह कदम सही साबित हुआ है और इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिली। महंगाई के मोर्चे पर स्थिरता आने के बाद फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट को स्थिर रखा गया।

बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों में सकारात्मक बदलाव - साल 2023 में देश में बेरोजगारी दर कम करने में भी बड़ी सफलता मिली है। एनएसएसओ की ताजा आवधिक श्रम बल रिपोर्ट देश में 15 साल से अधिक उम्र के नागरिकों में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत दर्ज की गई यह छह साल में सबसे कम है। पिछले साल बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत थी। वहीं 2020-21 में यह दर 4.2 प्रतिशत, 2019-20 में 4.8 प्रतिशत और 2018-19 में 5.8 और 2017-18 में 6 प्रतिशत थी। कामकाजी उम्र की कुल आबादी में 57.9 प्रतिशत लोग श्रम शक्ति में भागीदारी कर रहे हैं। यह संख्या 2017-18 में 49.8 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 50.7 से बढ़कर 60.8 प्रतिशत तो शहरों में 47.6 प्रतिशत से 50.4 प्रतिशत हुई है। पुरुषों की 78.5 प्रतिशत संख्या श्रम शक्ति में भागीदारी कर रही है, यह संख्या 2017-18 में 75.8 प्रतिशत थी। 37 प्रतिशत महिलाएं ही श्रम शक्ति का हिस्सा हैं, 2017-18 में इनकी संख्या 23.3 प्रतिशत थी। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि गांवों में बेरोजगारी कम है। यहां 2017-18 में 5.3 प्रतिशत बेरोजगारी थी, 2022-23 में यह महज 2.4 प्रतिशत रह गई। शहरों में इसी दौरान बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत से घट कर 5.4 प्रतिशत पर आई।

सीबीडीसी का सफल प्रयोग - आरबीआई की ओर से लॉन्च की गई डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के लिहाज से भी साल 2023 अहम साबित हुआ है। देश के चुनिंदा शहरों कें सीबीडीसी की लॉन्चिंग के बाद इसके प्रति लोगों में उत्साह दिखा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) या ई-रुपये के सीमापार लेन-देन के उपयोग से लागत में दो से तीन फीसदी की बचत होती है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा, सीबीडीसी का उपयोग कारोबार, पैसा भेजने या किसी और इस्तेमाल में भी सीमापार के लिए किया जा सकता है। सेठ ने कहा, फिलहाल, सीमापार भुगतान की बहुत कुशल प्रणाली नहीं है। इसमें समय लगता है। अप्रवासी भारतीय हर साल भारत में करीब 100 अरब डॉलर भेजते हैं।

जी-20 समिट का सफल आयोजन - साल 2023 भारत की अध्यक्षता में जी 20 के सफल आयोजन के लिए भी जाना जाएगा। जी 20 समिट के दौरान 115 से अधिक देशों से आए 25 हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने देशभर के 60 शहरों में 220 से ज्यादा मीटिंग की। भारत की अध्यक्षता में हुई जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का आपना संदेश पूरी दुनिया को दिया। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते या एफटीए की दिशा में भी साल 2023 में अहम बातचीत हुई। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम आने उम्मीद है।

आर्थिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा - भारत की अध्यक्षता में हुई जी20 समिट की एक अहम उपलब्धि आर्थिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा रही। यह कॉरिडोर जल्द ही भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच बनेगा। यह कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक और अपनी तरह की पहली पहल है। जिसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हो रहे हैं। इस कॉरिडोर के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इटली ने हाल ही में चीन के बीआरई प्रोजेक्ट से अलग होने की घोषणा कर दी है। यह रणनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

फंड जुटाने के लिए आकर्षक जमा योजनाएं लाएं बैंक

धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई पर दिया गया जोर

नई दिल्ली।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों से जनता से ज्यादा जमा राशि जुटाने के लिए नवीन और आकर्षक योजनाएं लाने के लिए कहा। इससे बैंकों को ज्यादा कर्ज देने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने धोखाधड़ी और जानबूझकर चूक करने वालों से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पिछले कई महीनों से बैंकों की जमा और कर्ज की वृद्धि में तालमेल नहीं बन पा रहा है। इस कारण बैंकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सावधि जमा दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ बैंकों की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर अभी भी 3-4 प्रतिशत है। एक बयान के अनुसार, वित्त मंत्री ने बैंकों के प्रदर्शन में सुधार पर संतोष जताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक धोखाधड़ी व्यक्तिगत ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। इससे वित्तीय नुकसान हो सकता है और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो सकता है।

वित्त मंत्री ने बैंकों से बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड और जानबूझकर चूक करने वालों के साथ धोखा देने वाले व्यक्तिगत ग्राहकों पर कार्रवाई के लिए ध्यान केंद्रित करने को कहा। साथ ही बैंकों को एडवांस्ड धोखधड़ी रोकथाम और पहचान तंत्र अपनाने का निर्देश दिया। बैठक में साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं और वित्तीय क्षेत्र पर इसके जोखिमों को लेकर चर्चा की गई। आधिकारिक बयान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान सरकारी बैंकों को 68,500 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकों की बैलेंस शीट में जमा और कर्ज वितरण के लिहाज से स्वस्थ वृद्धि रही है। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए एक दशक के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर रहा था, जो सितंबर में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गया है।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को मिली नई जिम्मेदारी, अब संभालेंगे यह अहम पद

नई दिल्ली।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय से जुड़े ऋत्विक रंजनम पांडे वित्त आयोग के सचिव होंगे। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि या 31 अक्टूबर, 2025, जो भी पहले हो तक पद पर बने रहेंगे। गौरतलब हैं कि वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के बारे में सिफारिशें करता हैं। अधिसूचना के मुताबिक, आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित धन के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उसके बाद उचित सिफारिशें कर सकता है। भारत सरकार द्वारा मार्च 2012 में डॉ. पनगढ़िया को पद्मभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हैं। इन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की हैं। विश्व बैंक, आईएमएफ जैसे विश्वस्तरीय संस्थानों में कई पदों पर वह कार्यरत रह चुके हैं। प्रोफेसर पनगढ़िया को भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। वे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरविंद पनगढ़िया को नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन दो वर्ष बाद उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाने वापस चले गए थे। जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक अरविंद पनगढ़िया ने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इन वर्षों के दौरान उन्होंने भारत के जी20 शेरपा के रूप में भी काम किया है। 1978 से 2003 तक कॉलेज पार्क में मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के संकाय में थे।

महिला के सैंडविच में कीड़ा, दिल्ली से मुंबई जाने वाले विमान की घटना; वीडियो देख एयरलाइंस ने कही यह बात

नई दिल्ली।

इंडिगो की महिला यात्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर सैंडविच में कीड़ा मिलने की शिकायत की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ान संख्या 6श्व 6107 में स्नैक्स खरीदने पर परोसे गए सैंडविच का जिक्र करते हुए महिला ने बताया कि सैंडविच में कीड़ा मिला। घटना के बाद एयरलाइंस ने माफी मांगी और कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है। महिला यात्री खुशबू गुप्ता ने फ्लाइट में खरीदी गई सैंडविच में कीड़े का वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर किया। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा, दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ान संख्या- 6ई 6107 में महिला यात्री के अनुभव और चिंता से कंपनी अवगत है। गौरतलब है कि इंस्टाग्राम हैंडल वीडियो में महिला यात्री ने एयरलाइंस की तरफ से परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केबिन क्रू को कीड़ा मिलने की सूचना दी गई। इसके बावजूद कर्मचारियों ने अन्य यात्रियों को सैंडविच बांटना जारी रखा।

महिला यात्री खुशबू गुप्ता ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि कर्मचारियों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे खाद्य पदार्थों के कारण अगर किसी को संक्रमण हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा इंस्टा प्रोफाइल पर लिखे विवरण के मुताबिक महिला डाइटिशियन हैं। सेहत और सौंदर्य से जुड़े विषयों पर क्लिनिकल एडवाइजर खुशबू गर्भवती महिलाओं को सलाह भी देती

हैं। वीडियो को 18 हजार से अधिक लाइक मिल चुके हैं। दर्जनों लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं।

वीडियो सामने आने पर एयरलाइंस ने कही यह बात

पूरे मामले पर प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, मामले की जांच के बाद हमारे दल ने संबंधित विशिष्ट सैंडविच की सेवा तुरंत बंद कर दी थी। मामले की अभी गहन जांच की जा रही है। इंडिगो की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, यात्रियों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर उचित सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। कंपनी अपने कैटरर के साथ मिलकर काम कर रही है। यात्रियों को हुई किसी भी असुविधा के लिए विमानन कंपनी ईमानदारी से माफी मांगती है।

आईफोन यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे को-पायलट ऐप

माइक्रोसॉफ्ट का एआई ऐप आईओएस यूजर्स के लिए लॉन्च, जीडीपी -4 मॉडल का फ्री एक्सेस मिलेगा

नई दिल्ली।

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ऐपल के आईओएस यूजर्स के लिए नया को-पायलट ऐप लॉन्च किया है। यानी आईफोन और आईपैड यूजर्स इस ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने हाल ही में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इसे पेश किया था। अब यह ऐपल के ऐप स्टोर पर यह नई ऐप डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो गई है। कोपायलट ऐप का उपयोग वही यूजर्स कर पाएंगे, जो अपने डिवाइस को आईओएस 15, आईपैडओएस 15 या बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला रहे हैं।

सर्च इंजन बिंग से अलग है यह ऐप

इस ऐप के जरिए यूजर अपने एआई चैटबॉट को एक नई सर्विस के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। यह ऐप सर्च इंजन बिंग से अलग है और पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ महीने पहले बिंग चैट का नाम बदलकर को-पायलट कर दिया था।

शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट का एआई बिंग सर्च इंजन का पार्ट था, जिसके सर्च रिजल्ट का इंटरफेस चैट-जीपीटी की तरह दिखता था। यह फीचर अब भी अवेलेबल है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट को एक अलग प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रमोट कर रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट क्या-क्या काम करता है

फंक्शनालिटी की बात करें तो

माइक्रोसॉफ्ट के इस को-पायलट में चैट-जीपीटी की तरह ही सिमिलर फीचर्स हैं यह ओपन-एआई के लेटेस्ट जीडीपी -4 मॉडल का फ्री एक्सेस देता है। यह ऐप चैटबॉट के साथ इंटरेक्शन करने की सुविधा देता है। मदद से इमेज क्रिएट करने के साथ-साथ ईमेल लिखने और डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट के इस असिस्टेंट में वॉइस इनपुट देने का ऑप्शन भी मिल जाता है। चीजों को सर्च या एक्सेस करने के लिए ऐप में इमेज और टेक्स्ट इनपुट का ऑप्शन भी मिलता है।

गूगल प्लेस्टोर पर 5 हजार से ज्यादा डाउनलोड्स

नया को-पायलट ऐप गूगल प्ले-स्टोर पर अवेलेबल है और 5 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। फिलहाल इसका आईओएस वर्जन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंपनी के मुताबिक, यह जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। तबतक, आईओएस यूजर्स बिंग ऐप पर को-पायलट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अभी चैटजीपीटी सबसे आगे

एआई की दुनिया में फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के बड़े निवेश वाली कंपनी ओपनएआई का चैटजीपीटी सबसे आगे है। चैटजीपीटी को पिछले साल 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था और एक महीने के भीतर इसके यूजर्स की संख्या दस करोड़ को पार कर गई थी। गूगल का चैटबॉट बार्ड के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है।

कोई भी सवाल पूछ सकते हैं

चैटजीपीटी से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यानी ईमेल लिखने से लेकर तक आप इससे बनवा सकते हैं। रील या अपनी वीडियो कैसे वायरल करना है, इसका भी जवाब चैटजीपीटी देता है। वाइफ को क्या गिफ्ट दें, इसके लिए सलाह भी आप चैट चैटजीपीटी से ले सकते हैं। सुंदर पिचाई 2016 में गूगल के सीईओ बने तो घोषणा की थी कि उनके लिए गूगल सबसे पहला एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) है। यह भी भविष्यवाणी की थी कि एआई का प्रभाव बिजली या आग से बड़ा होगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एआई चैटबॉट चैटजीपीटी लॉन्च किया और यह सुर्खियों में आ गया। इसकी क्षमता और सीमाओं को लेकर नई बहस छिड़ गई।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017